भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3718
उत्तर देने की तारीख 18 दिसम्बर, 2024

बीएसएनएल में बुनियादी ढांचे में सुधार

3718. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत सरकारी दूरसंचार नेटवर्क (बीएसएनएल) तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से सरकार द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे में सुधार कार्यों का राज्यवार तथा जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश भर में इंटरनेट कवरेज बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों में विशेष प्रयास किए गए हैं और यदि हां, तो राज्यवार तथा जिलावार कितने नए इंटरनेट तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्थापित किए गए हैं;

(ग) ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट तथा डिजिटल शिक्षा का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा किन योजनाओं तथा विशेष पहलों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) परियोजना में राज्य सरकारों द्वारा दिया गया प्रमुख योगदान क्या है तथा उक्त सहयोग के माध्यम से किन मुद्दों का समाधान किया गया है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सरकार डिजिटल भारत निधि (पूर्ववर्ती यूएसओएफ) के तहत विभिन्न परियोजनाओं को लागू कर रही है। बीएसएनएल को सौंपी गई ऐसी परियोजनाओं में (i) पूरे देश के सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 4जी सेच्युरेशन परियोजना, (ii) सीमा चौकियों/सीमा आसूचना चौकियों पर 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए सीमा चौकी (बीओपी)/सीमा आसूचना चौकी (बीआईपी) परियोजना। परियोजनाओं का विवरण वेबसाइट www.usof.gov.in पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल भारत निधि (पूर्ववर्ती यूएसओएफ) द्वारा वित्तपोषित की जा रही भारतनेट परियोजना (जिसे पहले राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता था) को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। आठ राज्यों (छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना) में भारतनेट चरण-II को राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। डीबीएन जीपीओएन (गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क) प्रौद्योगिकी के साथ लीनियर आर्किटेक्ट के लिए वित्तपोषण कर रहा है, हालांकि, कुछ राज्यों (महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़) ने राज्य सरकार के अंशदान के साथ आईपी-एमपीएलएस (इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग) प्रौद्योगिकी के साथ उन्नत रिंग आर्किटेक्चर को लागू किया है।

इसके अलावा, संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 04.08.2023 को 1.39 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 करोड़ हाई स्पीड एफटीटीएच ब्रॉडबैंड कनेक्शनों के प्रावधान सहित सभी ग्राम पंचायतों में और मांग के आधार पर गांवों में फाइबर का विस्तार किया जाएगा। इस स्कीम के लिए बीएसएनएल परियोजना प्रबंधन एजेंसी है। दिनांक 04.11.2024 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में भारतनेट नेटवर्क पर कुल 11,74,536 ब्रॉडबैंड एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत लागू की जा रही स्कीमों/परियोजनाओं में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी दिशा), राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) और भाषिणी आदि शामिल हैं।

*****